संपत्ति कर आयुक्त, लखनऊ

बनाम

पी.के बनर्जी (मृत) विधिक प्रतिनिधि द्वारा

9 सितंबर 1980

[पी. एन. भगवती. ई. एस. वैंकेटरमैया जे. जे.]

सम्पति कर अधिनियम 1957 धारा-2 (ई) (iv) वार्षिकी का दायरा-संपति कर अधिनियम के तहत छूट का दावा करने के लिये वार्षिकी के अन्तर्गत आने वाली राशि की प्रकृति को समझाया

प्रतिवादी निर्धारिती को अपने पिता प्यारे लाल बनर्जी द्वारा निष्पादित 26 अक्टूबर 1937 के.एक.ट्रस्ट डीड के तहत जिसे 28 अप्रेल 1950 को एक अन्य ट्रस्ट डीड द्वारा संशोधित किया गया था।

"अपने पिता की मृत्यु के बाद ट्रस्ट फण्ड की मुख्य आय" प्राप्त हुयी। निर्धारिती ने इस राशि को वार्षिकी के रूप में माना और सम्पति कर अधिनियम 1957 की धारा 2 (ई) (iv) के तहत छूट का दावा किया। छूट के दावा को अपीलीय न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ सहित सभी अधिकारियों ने खारिज कर दिया। हालांकि न्यायाधिकरण ने यह मानते हुये कि शुद्ध सम्पति की गणना में कोरपस के सम्पूर्ण मूल्य को शामिल करना सही नहीं था क्योंकि निर्धारिती का इसमें केवल जीवन हित था। सम्पति कर अधिकारी को मान्यता प्राप्त अनुसार निर्धारिति के जीवन हित का मूल्याकंन करते हुये मूंल्याकन को संशोधित करने का निर्देश दिया। मूल्यांकन के सिद्धांत एक संदर्भ में, निर्धारिती के उदाहरण पर उच्च न्यायालय ट्रस्ट फण्ड में निर्धारिती के हित को सम्पति कर अधिनियम की धारा 2(ई)(iv) के तहत वार्षिकी छूट के बराबर माना।

विशेष अनुमति द्वारा अपील की अनुमति देना और निर्धारिती के खिलाफ जबाब देना।

अभिनिर्धारित किया:

(1) यह दावा करने के लिये की सम्पति की एक वस्तु को सम्पति कर अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सम्पति के रूप में नहीं माना जाना चाहिये। धारा 2 (ई) (1)के उपखण्ड (4) के आधार पर, यह है। सुस्थापित किया जाना चाहिये (ए) की यह एक वार्षिकी है और (बी) की इसके किसी भी हिस्से को एक मुश्त अनुदान में परिवर्तित करना इसके नियमों और शर्तो से वर्जित है।

(2) यह सच है कि अधिनियम में वार्षिकी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है एक वार्षिकी का गठन करने के लिये, समय समय पर किये जाने वाला भुगतान एक निश्चित या पूर्व निर्धारित होना चाहिये और यह फण्ड या सम्पति की सामान्य आय से संबंधित किसी भी आधार पर किसी भी बदलाव के लिये उत्तरदायी नहीं होना चाहिये। ऐसे भुगतान के लिये शुल्क लिया जाता है। सेटलर की मंशा जरूर देखनी चाहिये कि क्या वह चाहता था। कि करदाता को हर साल पूर्व निर्धारित राशि मिले या कर दाता को ट्रस्ट फण्ड की पूरी शुद्ध आय मिले।

तत्काल मामले में, चूंकि निपटान कर्ता का हित यह था कि ट्रस्ट फण्ड की पूरी शुद्ध आय निर्धारिती के पास जानी चाहिये इसलिये निर्धारिती के अधिकार के वार्षिकी के रूप में नहीं माना जा सकता है। तथ्य यह है कि ट्रस्ट डीड के तहत ट्रस्टी को सरकारी प्रतिभूतियों की आय को फिर से निवेश करने की शक्ति दी गयी थी जिससे आय में भिन्नता की संभावना होती है और परिणामस्वरूप को निर्धारिती को प्राप्त होने वाली राशि में भिन्नता होती है यह स्पष्ट है कि ऐसा नहीं था एक वार्षिकी यह तथ्य की प्रासंगिक वर्ष के दौरान ऐसा कोई पुनर्निवेश नहीं हुआ था, महत्वहीन है।

अहमद जी.एच. एवं अन्य बनाम धन-कर आयुक्त, कलकता (1970)76 आई.टी.आर.471 संपति कर आयुक्त, गुजरात द्वितीय बनाम श्रीमती अरूंधती बालकृष्ण(1968) 70 आइ.टी.आर.203, समझाया व लागू किया गया।

धन-कर आयुक्त, राजस्थान बनाम जयपुर की महारानी गायत्री देवी(1971) 82 आइ.टी.आर. 699 अनुसरण किया गया।

सम्पति कर आयुक्त ए.पी. बनाम नवाब फरीद नवाज गंज और अन्य (1970)77 आइ.टी.आर.180 खारिज कर दिया गया।

इनरी डयूक ऑफ में सार्वजनिक ट्रस्टी बनाम अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त (1950) सीएच. 467

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:- सिविल अपील संख्या 1167-1167/1973

सम्पति कर अपील संख्या 232/1964 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 15-03-971 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील,

अपीलकर्ता की और से एस.टी. देसाई. और सुश्री ए शुभासिनी

प्रतिवादी की और से एस.एन.काकर,के.पण्डित और इ.सी. अग्रवाल

वेंकटरमैया,जे.:-

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें 15 मार्च 1971 के फैसले के खिलाफ निर्देशित हैं। 15 मार्च 1971 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के धन कर संदर्भ संख्या 232 ऑफ 1964 में।

मामले के तथ्यों को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है: आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, इलाहाबाद बेंच, इलाहाबाद के तहत संदर्भित किया गया है मूल्यांकन के संबंध में अधिनियम के तहत किए गए मूल्यांकन आदेशों से उत्पन्न होने वाले कानून के निम्नलिखित प्रश्न पर संपत्ति कर अधिनियम, 1957 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 27 (1) के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय को उसकी राय के लिए भेजा गया है। वर्ष 1957-58 से 1961-62

"क्या ट्रस्ट फंड में निर्धारिती का ब्याज संपत्ति कर अधिनियम की धारा 2 (ई) (iv) सम्पति कर अधिनियम के तहत वार्षिकी छूट के बराबर है?"

इस मामले में संबंधित निर्धारिती श्री पी.के.बनर्जी हैं, उनके पिता श्री प्यारे लाल बनर्जी (बाद में सेटलर के रूप में संदर्भित) द्वारा निष्पादित दिनांक 26 अक्टूबर, 1937 के एक ट्रस्ट डीड के तहत, निर्धारिती उत्पन्न होने वाली आय प्राप्त करने का हकदार बन गया। सेटलर की मृत्यु के बाद उसके (निर्धारिती) जीवनकाल के दौरान ट्रस्ट फंड की ऐसी आय से दो अन्य व्यक्तियों को समय-समय पर विलेख में उल्लिखित कुछ निर्दिष्ट रकम का भुगतान करने के दायित्व के अधीन। निर्धारिती की मृत्यु के बाद, ट्रस्ट फंड की आय को ऊपर उल्लिखित दो अन्य व्यक्तियों को समान शेयरों में भुगतान करने का निर्देश दिया गया था और यदि उनमें से किसी की भी निर्धारिती की मृत्यु से पहले मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी पूरी आय का भुगतान करना होगा। उनमें से जीवित बचे व्यक्ति को उसके जीवन के दौरान भुगतान किया जाएगा। ट्रस्ट फंड से उत्पन्न होने वाली आय के निपटान के संबंध में ट्रस्ट डीड में कुछ अन्य निर्देश थे जिनसे हम इस मामले में चिंतित नहीं हैं। ट्रस्ट फंड में समय-समय पर जारी किए गए कुछ भारत सरकार के ऋण बांड या प्रतिभूतियां शामिल थीं, जिसके तहत कुछ निर्दिष्ट ब्याज देय था। ऐसे बांडों का कुल अंकित मूल्य रु. 10 लाख. इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, कलकत्ता (इसके बाद ट्रस्टी के रूप में संदर्भित) को ट्रस्ट डीड के तहत ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया था और ऊपर उल्लिखित सरकारी ऋण बांड या प्रतिभूतियों को दायित्वों के निर्वहन की दिशा के साथ ट्रस्टी के पक्ष में स्थानांतरित और समर्थन किया गया था।

ट्रस्ट डीड में संदर्भित। ट्रस्ट डीड के खंड (1) के तहत, सेटलर ने ट्रस्टी को उक्त सरकारी ऋण बांड या प्रतिभूतियों को अपने पास रखने और उनमें से किसी को भुनाने पर उससे प्राप्त आय को साढ़े तीन प्रतिशत सरकारी वचनपत्र की खरीद में निवेश करने का निर्देश दिया। नोट्स (पुराना अंक) या यदि यह भारत सरकार की किसी अन्य सुरक्षा में व्यवहार्य नहीं था या यदि यह भी व्यावहारिक नहीं था तो भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 या किसी वैधानिक संशोधन द्वारा ट्रस्ट फंड के निवेश के लिए अधिकृत किसी अन्य प्रतिभूतियों में तत्संबंधी और सरकारी ऋण बांड या ऊपर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों या ट्रस्ट फंड के समान प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी अन्य निवेश को विलेख में निहित निर्देशों के अनुसार उपयोग करने के लिए धारण करना और अपने पास रखना। 26 अक्टूबर, 1937 के ट्रस्ट डीड के प्रासंगिक विवरण निम्नलिखित हैं जिसमें ट्रस्ट फंड से उत्पन्न होने वाली आय को विनियोजित या खर्च करने के तरीके के बारे में निर्देश शामिल हैं

> ‘‘(ए) अपने जीवन के दौरान ट्रस्ट फंड की शुद्ध आय सेटलर को भुगतान करेगा और उसे सीधे भुगतान करने के बजाय, उसे बैंक के साथ सेटलर के चालू खाते में जमा कर सकता है, जब तक कि ऐसा कोई चालू खाता मौजूद रहे।

(बी) सेटलर की मृत्यु से और उसके बाद, बैंक सेटलर के बेटे प्रणब कुमार बनर्जी को उनके जीवन के दौरान ट्रस्ट फंड की शुद्ध आय का भुगतान करेगा, अगर वह भुगतान के अधीन सेटलर के रूप में जीवित रहना चाहिए इसके बाद, हर छह महीने में अप्रैल के तीसवें दिन और अक्टूबर के इकतीसवें दिन, बसने वाले के बेटे सुनबकुमार बनर्जी को नौ सौ रुपये और बसने वाली बहू पूर्णिमा बनर्जी को छह सौ रुपये की राशि दी जाती है। अपने जीवन के दौरान, यदि वह सेटलर से बचजाएगा।

(सी) यदि उक्त प्रणब कुमार बनर्जी सेटलर की मृत्यु से पहले हो जाएंगे या यदि सेटलर के जीवित रहने के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो पहले मामले में सेटलर की मृत्यु से और बाद के मामले में उक्त प्रणब कुमार बनर्जी की मृत्यु पर और उसके बाद से, ट्रस्ट फंड की आय उक्त सनब कुमार बनर्जी और पूर्णिमा बनर्जी (यदि वह जीवित है) या ऐसी पूरी आय को समान शेयरों में भुगतान किया जाएगा। अपने जीवन के दौरान उनमें से जीवित बचे व्यक्ति।

(डी) यदि उक्त प्रणब कुमार बनर्जी, सुनब कुमार बनर्जी और पूर्णिमा बनर्जी सेटलर से पहले मर जाएंगे या यदि वे या उनमें से कोई एक या अधिक सेटलर से जीवित रहने के बाद मर जाएंगे, तो पूर्व में निपटानकर्ता की मृत्यु के मामले में और बाद के मामले में उक्त प्रणब कुमार बनर्जी, सुनब कुमार बनर्जी और पूर्णिमा बनर्जी के उत्तरजीवी की मृत्यु के बाद, बैंक ट्रस्ट फंड और उसकी आय पर कब्ज़ा कर लेगा। ऐसे ट्रस्ट, जैसा कि प्रणब कुमार बनर्जी किसी भी कार्य या कार्य द्वारा निरस्तीकरण की शक्ति के साथ या उसके बिना नियुक्त कर सकते हैं या वसीयत या कोडिसिल द्वारा किसी भी समय या समय पर नियुक्त कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट रूप से और जहां तक ऐसी कोई नियुक्ति होगी, ट्रस्ट में विस्तार नहीं किया जाएगा। बसने वाले के भतीजे मनोज कुमार बनर्जी और बसने वाली की भतीजी झूनी बनर्जी (अब नाबालिग), यदि वे दोनों जीवित हैं, या दोनों में से कोई एक जीवित हो और उस व्यक्ति या उन दोनों के लिए डिफ़ॉल्ट हो, जो निर्वसीयत से संबंधित कानून के तहत हैं बंदोबस्तकर्ता की मृत्यु पर उत्तराधिकार उसका हकदार होता, यदि बंदोबस्तकर्ता की मृत्यु उसके कब्जे में और बिना वसीयतकिए हई होती।"

26 अक्टूबर, 1937 को इसकी शर्तों को संशोधित करने के लिए, सेटलर ने 28 अप्रैल, 1950 को एक और ट्रस्ट डीड निष्पादित किया, जिसके द्वारा ऊपर निकाले गए 26 अक्टूबर, 1937 के ट्रस्ट डीड के खंड (बी) और (सी) को निम्नलिखित खंडों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था;

(बी) सेटलर की मृत्यु से और उसके बाद बैंक सेटलर के बेटे प्रणब कुमार बनर्जी को उनके जीवनकाल के दौरान ट्रस्ट फंड की शुद्ध आय का भुगतान करेगा। यदि वह आबादकार से बच जाए।

(सी) संरेखित करें यदि उक्त प्रणब कुमार बनर्जी वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले मृत हो जाए या यदि वह सेटलर के जीवित रहने के बाद मर जाएगा, तो पहले मामले में सेटलर की मृत्यु से और बाद के मामले में, उक्त प्रणब कुमार बनर्जी की मृत्यु से ट्रस्ट फंड की आय मेरे बेटे सुनब कुमार बनर्जी और मेरी बहू शकुंतला बनर्जी (यदि वह जीवित है) पूरी को बराबर शेयरों में दी जानी चाहिए था या उनमें से जीवित बचे व्यक्ति को उसके जीवन के दौरान ऐसी सम्पूर्ण आय।

26 अक्टूबर 1937 के ट्रस्ट डीड के खंड

(डी) में पूर्णिमा बनर्जी का नाम, 28 अप्रैल 1950 के ट्रस्ट डीड द्वारा शकुंतला बनर्जी नाम से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। परिणामी स्थिति यह थी कि ट्रस्टी को अपने जीवनकाल के दौरान सेटलर को ट्रस्ट फंड की शुद्ध आय का भुगतान करना था और उसकी मृत्यु के बाद ट्रस्टी को अपने जीवनकाल के दौरान ट्रस्ट फंड की शुद्ध आय का भुगतान सेटलर को करना था, यदि वह सेटलर के जीवित रहना चाहता था। यदि निर्धारिती को सेटलर की मृत्यु से पहले ही मर जाना चाहिए और उसके बाद सेटलर की मृत्यु हो जानी चाहिए और यदि निर्धारिती की मृत्यु सेटलर के बाद और उसके बाद हो जाती है, तो ट्रस्ट फंड की आय का भुगतान समान शेयरों में किया जाना चाहिए सुनब कुमार बनर्जी, सेटलर का दूसरा बेटा और शकुंतला बनर्जी, सेटलर की बहू (यदि वह जीवित है) और इस तरह की पूरी आय उनके जीवित रहने के दौरान जीवित बचे व्यक्ति को दी जानी थी। या उसका जीवन. हम इस मामले में मुख्य रूप से 28 अप्रैल, 1950 के ट्रस्ट डीड द्वारा प्रतिस्थापित ट्रस्ट डीड के खंड (बी) द्वारा निर्धारिती को दिए गए लाभ के चरित्र से चिंतित हैं। सेटलर की 1952 में किसी समय मृत्यु हो गई और तब से करदाता की मृत्यु हो गई। एकमात्र लाभार्थी के रूप में उक्त खंड के अनुसार ट्रस्ट फंड से शुद्ध आय प्राप्त करना। प्रश्नगत मूल्यांकन वर्षों से संबंधित अधिनियम के तहत मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान, निर्धारिती ने संपत्ति कर अधिकारी, इलाहाबाद के समक्ष तर्क दिया कि चूंकि ट्रस्ट फंड का कोष ट्रस्टी में निहित था, न कि उसमें, ट्रस्ट

फंड का मूल्य उसकी कुल संपत्ति में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में क्योंकि उसे ट्रस्ट डीड के तहत केवल वार्षिकी प्राप्त करने का अधिकार था, ट्रस्ट फंड को इस कारण से ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए अधिनियम की धारा 2 (ई) (iv). संपत्ति कर अधिकारी ने निर्धारिती की दलीलों को खारिज कर दिया और उसके द्वारा पारित सभी पांच मूल्यांकन आदेशों में निर्धारिती की कुल संपत्ति में ट्रस्ट फंड का पूरा बाजार मूल्य शामिल किया। संपत्ति कर के अपीलीय सहायक आयुक्त, इलाहाबाद के समक्ष निर्धारिती द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई। आगे की अपील पर, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, इलाहाबाद खंडपीठ,जहां तक संपत्ति कर अधिनियम की धारा 2 (ई) (iv) की गैर-प्रयोज्यता का सवाल है, लेकिन यह माना गया कि शुद्ध संपत्ति की गणना में कॉर्पस के पूरे मूल्य को शामिल करना सही नहीं था क्योंकि निर्धारिती का इसमें केवल जीवन हित था। तदनुसार, इसने संपत्ति कर अधिकारी को मूल्यांकन के मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के अनुसार निर्धारिती के जीवन हित का मूल्यांकन करते हुए मूल्यांकन को संशोधित करने का निर्देश दिया। इसके बाद निर्धारिती के कहने पर, ऊपर निर्धारित कानून का सामान्य प्रश्न अधिनियम की धारा 27 (1) के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय को भेजा गया था। पांच मूल्यांकन वर्षों से संबंधित सभी पांच संदर्भों को वर्ष 1970 में उच्च न्यायालय द्वारा एक साथ सुना गया था। चूंकि उच्च न्यायालय का विचार था कि मामले का पूरक विवरण प्रस्तुत करने के लिए आयकर

अपीलीय न्यायाधिकरण को निर्देश देना आवश्यक था। निम्नलिखित प्रश्नों पर:

"(1) क्या ऊपर उल्लिखित ट्रस्ट के कार्यों के संदर्भ में राशि प्राप्त करने का निर्धारिती का अधिकार अधिनियम की धारा

2 (ई) (iv) के अर्थ में एक 'वार्षिक' है और यदि हां,

(2) तो क्या ऐसी वार्षिकी से संबंधित नियम और शर्तें उसके किसी भी हिस्से को एकमुश्त अनुदान में परिवर्तित करने से रोकती हैं?

इसने ट्रिब्यूनल को 27 फरवरी, 1970 के अपने आदेश द्वारा उपरोक्त प्रश्नों पर मामले का एक पूरक विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, ट्रिब्यूनल ने अगस्त, 1970 में मामले का एक पूरक विवरण प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि विचाराधीन संपत्ति अधिनियम की धारा 2 (ई) (iv) में निर्दिष्ट वार्षिकी नहीं थी। इसके बाद मामलों की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा की गई। 15 मार्च 1971 के अपने निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने निर्धारिती के पक्ष में संदर्भित कानून के सामान्य प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया, यह मानते हुए कि ट्रस्ट फंड में निर्धारिती का ब्याज अधिनियम धारा 2 (ई) (iv) के तहत वार्षिकी छूट के बराबर है। उच्च न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट विभाग ने इस न्यायालय में अपील की है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अधिनियम के तहत कर योग्य संपत्तियों के मामले में, जो एक ट्रस्टी द्वारा विधिवत निष्पादित लिखित दस्तावेज के तहत रखी गई हैं, चाहे वह वसीयतनामा हो या अन्यथा, संपत्ति कर सीधे लगाया जा

सकता है और उस व्यक्ति से वसूली योग्य है जिसकी ओर से संपत्तियां रखी गई हैं। अधिनियम की धारा 3 प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार और कंपनी की संबंधित मूल्यांकन तिथि पर शुद्ध संपत्ति के संबंध में अधिनियम की अनुसूची। में निर्दिष्ट दर या दरों पर उक्त शुल्क बनाती है। धारा के अनुसार शुद्ध संपत्ति। अधिनियम के 2 (एम) का अर्थ वह राशि है जिसके द्वारा मूल्यांकन तिथि पर निर्धारिती से संबंधित सभी संपत्तियों, जहां भी स्थित हो, के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुल मूल्य की गणना की जाती है, जिसमें उसके शुद्ध में शामिल करने के लिए आवश्यक संपत्तियां भी शामिल हैं। अधिनियम के तहत उस तारीख को संपत्ति, उसके उप-खंड (i) से (iii) में निर्दिष्ट ऋणों के अलावा मूल्यांकन तिथि पर निर्धारिती द्वारा बकाया सभी ऋणों के कुल मूल्य से अधिक है। अधिनियम की धारा 2 (ई) में, अभिव्यक्ति "संपत्ति" को हर विवरण की संपत्ति, चल या अचल के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन 1 अप्रैल, 1969 से शुरू होने वाले मूल्यांकन वर्ष या किसी भी पहले के मूल्यांकन वर्ष के संबंध में उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है। जिनका उल्लेख धारा 2 (ई) (1) के उप-खंड (i) से (v) में किया गया है। अधिनियम की धारा

2 (ई) (1) का उप-खंड (iv) जो इस मामले के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक है, संपत्ति शब्द की परिभाषा से किसी भी मामले में वार्षिकी का अधिकार बाहर कर देता है जहां इससे संबंधित नियम और शर्तें हैं उसके किसी भी हिस्से को एकमुश्त अनुदान में परिवर्तित करने पर रोक लगाएं। यह दावा करने के लिए कि संपत्ति की एक वस्तु को धारा 2 (ई) (1) के उप-खंड (iv) के आधार पर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपत्ति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, यह स्थापित करना होगा (i) कि यह एक वार्षिकी है और (ii) उसके किसी भी हिस्से को एकमुश्त अनुदान में परिवर्तित करना उससे संबंधित नियमों और शर्तों के तहत वर्जित है।

विचाराधीन संपत्ति निर्धारिती का उसके जीवनकाल के दौरान ट्रस्ट फंड की शुद्ध आय प्राप्त करने का अधिकार है। ट्रिब्यूनल के आदेशों से उभरने वाले प्राथमिक तथ्य हैं

(1) कि ट्रस्ट डीड के तहत, सेटलर का इरादा था कि सेटलर की मृत्यु के बाद, निर्धारिती अपने (करदाता) जीवनकाल के दौरान ट्रस्ट फंड से शुद्ध आय का एकमात्र लाभार्थी होना चाहिए।

(2) कि निर्धारिती अपने द्वारा देय आयकर के प्रयोजनों के लिए खुद को ट्रस्ट फंड के मालिक के रूप में मान रहा था और ट्रस्ट की आय को अपनी आय के रूप में घोषित कर रहा था और अपने स्वयं के आयकर रिटर्न में कटौती का दावा कर रहा था ट्रस्ट द्वारा स्रोत पर भुगतान किए गए कर के लिए;

(3) वास्तव में निर्धारिती ट्रस्ट फंड से प्राप्त शुद्ध आय का एकमात्र लाभार्थी था;

(4) कि ट्रस्ट डीड के तहत उन्हें कुछ परिस्थितियों में अपने उत्तराधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार था और

(5) ट्रस्टियों के पास सरकारी ऋण बांड या प्रतिभूतियों की आय को निवेश करने की शक्ति थी, जो उनके मोचन पर ट्रस्ट फंड का गठन करते थे। विलेख में प्रावधान किया गया था और इसलिए ट्रस्ट फंड से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय भिन्नता के अधीन थी। 26 अक्टूबर, 1937 के ट्रस्ट डीड की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह है कि निर्धारिती को जो देय था वह एक निश्चित पूर्व निर्धारित राशि का आवधिक भुगतान नहीं था, बल्कि केवल ट्रस्ट फंड की शुद्ध आय थी, हालांकि यह अनुमान लगाना संभव था किसी भी समय इस तरह की आय कुछ निश्चितता के साथ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तत्काल मामले में ट्रस्ट फंड में सरकारी ऋण बांड या प्रतिभूतियां शामिल थीं, जिनकी मोचन पर प्राप्त आय अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए उत्तरदायी थी जैसा कि संकेत दिया गया है। ट्रस्ट डीड दिनांक 26 अक्टूबर 1937

उच्च न्यायालय का इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कि प्रश्नांकित सम्पति एक वार्षिकी थी का मुख्य कारण अपने निर्णय में इस प्रकार निष्कर्षित किया गया है;

हमारे सामने मामले में ट्रस्ट डीड के तहत तय की गई संपत्ति में सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं, और डीड के साथ संलग्न अनुसूची से यह स्पष्ट है कि वे एक निश्चित और निर्धारित दरों पर ब्याज लेते हैं।

सेटलर ने प्रदान किया ट्रस्टी को सरकारी प्रतिभूतियों को भुनाने और प्राप्त राशि को 3,1/2 सरकारी वचन पत्र (पुराने अंक) की खरीद में या भारत सरकार की किसी अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने की शक्ति है, या यदि यह व्यवहार्य नहीं है तो अधिकृत किसी अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने की शक्ति है। भारतीय ट्रस्ट अधिनियम द्वारा ट्रस्ट फंड के निवेश के लिए। हमारे सामने यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि ट्रस्ट की संपत्ति वाली मूल प्रतिभूतियों को उन प्रतिभूतियों द्वारा परिवर्तित या प्रतिस्थापित किया गया था जो निश्चित ब्याज दर नहीं देते थे और एक निश्चित और निश्चित रिटर्न देते थे। आय। आगे बढ़ते हुए, इसलिए, इस आधार पर कि प्रतिभूतियों से एक निश्चित और निश्चित आय प्राप्त होती है, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि निर्धारिती को जो प्राप्त हुआ वह एक ऐसी राशि थी जो संपत्ति की सामान्य आय पर निर्भर नहीं थी या उससे संबंधित नहीं थी। इस अर्थ में कि आय में उतार-चढ़ाव के साथ इसमें उतार-चढ़ाव होता रहा। ट्रस्ट के तहत तय की गई संपत्ति के चरित्र और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ट्रस्ट की संपत्ति से उत्पन्न आय की मात्रा में वृद्धि या गिरावट का कोई सवाल ही नहीं उठता है और इसलिए, वास्तविक अर्थ में निर्धारिती जिस चीज का हकदार है वह निश्चित

है। और निश्चित राशि. साथ ही, ट्रस्ट डीड की शर्तों को ध्यान में रखते हुए यह कहना संभव नहीं है कि निर्धारिती का हित ट्रस्ट फंड की पूंजी में हित है। इसलिए, ड्यूक ऑफ नोरफोक में जानकिंस एलजे द्वारा निर्धारित परीक्षण पर: इन री: पब्लिक ट्रस्टी बनाम इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर। (1950) 1 अध्याय 467, इसे जीवन हित के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। हम कॉमरेड में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के कुछ तुलनीय तथ्यों पर लिए गए निर्णय से दृढ़ हैं। वेल्थ -टैक्स बनाम नवाब फरीद नवाज जंग, (1970) 77 आईटीआर 180।

यह सच है कि निर्धारिती केवल शुद्ध आय का हकदार है और क्योंकि ट्रस्टी को इसमें से कटौती करने का अधिकार है। सकल आय, उसका पारिश्रमिक, उसकी वार्षिक आय शुल्क और ट्रस्ट संपत्ति के प्रबंधन में खर्च, शुद्ध आय साल-दर-साल भिन्न हो सकती है। फिर भी यहां भी पारिश्रमिक और वार्षिक आय शुल्क ट्रस्टी द्वारा एक निश्चित दर पर ही लिया जा सकता है, और शुद्ध आय में किसी भी बदलाव को ट्रस्ट संपत्ति के प्रबंधन में साल-दर-साल अलग-अलग खर्चों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि भिन्नता से मुक्ति किसी वार्षिकी के चरित्र को निर्धारित करने वाली पूर्ण परीक्षा नहीं है। हमारी राय है कि जहां यह केवल ट्रस्ट के प्रशासन के कारण देय शुल्कों और खर्चों के कारण भिन्न होता है, यह वार्षिकी के रूप में अपना चरित्र नहीं खोता है। संरेखित करें उपरोक्त विचार पर, हमें ऐसा लगता है कि ट्रस्ट डीड के तहत ट्रस्ट संपत्ति से शुद्ध आय पर निर्धारिती के अधिकार को कानून में वार्षिकी के अधिकार के रूप में वर्णित किया जा सकता है ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने महसूस किया है कि मामले के तथ्य अहमद जीएच आरिफ बनाम वेल्थ टैक्स कमिश्नर, कलकत्ता, (1970) 76 आईटीआर 471 के तथ्यों से अलग थे: एआईआर 1971 एससी 1691) और कॉमरेड में तथ्य। संपत्ति कर, गुजरात ॥ बनाम श्रीमती अरुंधति बालकृष्ण, (1968) 70 आईटीआर 203 (गुजरात)। फिलहाल हम इन दो मामलों पर चर्चा करेंगे।

अधिनियम में वार्षिकी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अंग्रेजी कानून के शुरुआती कानूनी संकलनों में से एक में, वार्षिकी शब्द को एक निश्चित राशि के वार्षिक भुगतान के रूप में समझाया गया है जो किसी अन्य व्यक्ति को शुल्क के रूप में या जीवन भर के लिए या वर्षों की अवधि के लिए या तो व्यक्तिगत दायित्व के तहत देय होता है। अनुदानकर्ता या उसके शुद्ध व्यक्तित्व पर शुल्क लगाया जाता है, हालांकि यह उसकी फ्रीहोल्ड या लीजहोल्ड भूमि पर शुल्क लगाया जा सकता है, बाद वाले मामले में इसे आमतौर पर किराया-प्रभार कहा जाता है (कंपनी लिट। 144 बी देखें)। इंग्लैंड के हेल्सबरीज़ कानून में, तीसरा संस्करण (खंड 32, पृष्ठ 534 पैरा 899), उक्त अभिव्यक्ति का अर्थ सालाना देय एक निश्चित राशि के रूप में दिया गया है जो या तो अनुदानकर्ता के व्यक्तिगत दायित्व के रूप में या संपत्ति से बाहर है जो विशेष रूप से शामिल नहीं है ज़मीन का; यह लगान-प्रभार से इस मायने में भिन्न है कि लगान-प्रभार भूमि से जारी होता है। बिग्नोल्ड बनाम गाइल्स में, वार्षिकी का वर्णन इस प्रकार किया गया है:

"एक वार्षिकी एक निश्चित राशि प्रति वर्ष प्राप्त करने का अधिकार है; जीवन भर के लिए, या कई वर्षों के लिए दिया जा सकता है; यह किसी विशेष अवधि के दौरान, या अनंत काल के लिए दिया जा सकता है; और वार्षिकी के बारे में यह विलक्षणता भी है, कि यद्यपि व्यक्तिगत संपत्ति से भुगतान किया जाता है, फिर भी वे दिए जाने में सक्षम हैं हस्तांतरण के प्रयोजन के लिए, अचल संपत्ति के रूप में; वे एक आदमी और उसके उत्तराधिकारियों को दिए जा सकते हैं, और अचल संपत्ति के रूप में वारिस के पास जा सकते हैं; इसलिए एक आदमी और उसके शरीर के उत्तराधिकारियों को वार्षिकी दी जा सकती है; ऐसा नहीं है, यह सच है, एक एस्टेट टेल का गठन करता है, लेकिन यह क़ानून डी डोनिस के कारण है, जिसमें केवल टेनेमेंट शब्द शामिल है और एक वार्षिकी, हालांकि एक वंशानुगत है, एक टेनेमेंट नहीं है; और इस प्रकार दी गई वार्षिकी एक आधार शुल्क है।

उपरोक्त निर्णय में इसे इस प्रकार देखा गया है: 'लेकिन यह मुझे कम से कम स्पष्ट प्रतीत होता है, कि यदि जिसे वार्षिकी कहा जाता है उसका उपहार ऐसा है बनाया गया, कि, वसीयत के प्रथम दृष्टया ही, वसीयतकर्ता एक फंड के लाभांश का एक निश्चित हिस्सा देने का अपना इरादा दिखाता है, यह एक बहुत अलग बात है; और अधिकांश मामले उसी आधार पर आगे बढ़ते हैं। आधार यह है, अदालत का मानना कि वसीयतकर्ता का इरादा न केवल वार्षिकी देने का है, बल्कि एक निश्चित पूंजी निधि से उत्पन्न होने वाली आय का एक अंश देने का भी है।"

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 173 के तहत दिए गए तीन उदाहरण, जो वार्षिकी की वसीयत से संबंधित हैं, समय-समय पर कुछ निश्चित रकम के भुगतान का भी उल्लेख करते हैं और वे इससे उत्पन्न होने वाली आय के आवधिक भुगतान का उल्लेख नहीं करते हैं।

कोई ट्रस्ट फंड यह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि यह न्यायालय अहमद जीएच आरिफ के मामले का फैसला करने के लिए आगे बढ़ा (सुप्रा)। उस मामले में, न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए बुलाया गया था कि वक्फ-अलाल-औलाद बनाने वाले विलेख के तहत अपीलकर्ताओं को दिए गए लाभ वार्षिकियां थे या नहीं। विलेख का प्रासंगिक भाग, जिसमें घोषित किया गया था कि आबादकार के वंशजों की पूर्ण निर्वसीयत के मामले में अंतिम लाभ मदद के योग्य सुनी समुदाय के गरीब मुसलमानों के लिए आरक्षित था,

इस प्रकार पढ़ें:भुगतान के बाद उक्त वक्फ संपत्ति के रखरखाव और प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक व्यय, जैसे स्थापना शुल्क, संग्रह शुल्क, राजस्व कर, मरम्मत की लागत, कानून शुल्क और अन्य खर्च, मुतवल्ली या मुतवल्ली उक्त की शुद्ध आय को लागू करेंगे। वक्फ संपत्ति इस प्रकार है, अर्थात:

(ए) मुझे मेरे जीवन काल के दौरान उक्त शुद्ध आय का पांचवां हिस्सा मासिक किस्तों द्वारा भुगतान में;

(बी) मेरे प्रत्येक बेटे को उनके जीवन की संबंधित शर्तों के दौरान उक्त शुद्ध आय का छठा हिस्सा मासिक किस्तों द्वारा भुगतान में;

(सी) भुगतान में, मेरी पत्नी आयशा बीबी को, उसके जीवन काल के दौरान उक्त शुद्ध आय का दसवां हिस्सा मासिक किश्तों द्वारा।

मेरे ऐसे नाबालिग पुत्रों को देय धनराशि, जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते, क्रमशः उचित प्रतिभूतियों या भूमि संपत्ति में (उनके रखरखाव और शिक्षा के खर्चों को चुकाने के बाद) निवेश किया जाएगा। कलकत्ता में और ऐसी प्रतिभूतियाँ या संपत्ति उनके क्रमशः वयस्क होने पर उक्त पुत्रों को सौंप दीजाएगी ।

संपत्तियों की शुद्ध आय अधिनियम की धारा 2 (ई) की परिभाषा के तहत कवर की गई संपत्ति थी और केवल वार्षिकी नहीं थी और अहमद जीएच आरिफ बनाम वेल्थ टैक्स कमिश्नर, कलकत्ता में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की गई थी।

संरेखित करें श्रीमती अरुंधति बालकृष्ण (1968), 70 आईटीआर 203 (गुजरात) (सुप्रा) के मामले में, जिसमें हम में से एक एक पार्टी थी, निर्धारिती के पिता द्वारा बनाए गए दो ट्रस्टों के तहत और एक उसकी सास द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के लिए, उसे ट्रस्ट के प्रशासन की लागत और खर्चों में कटौती के बाद प्रत्येक ट्रस्ट की शुद्ध आय का सालाना भुगतान किया जाना था। निर्धारिती के जीवनकाल के बाद ट्रस्टों की शर्तों के तहत, प्रत्येक मामले में ट्रस्ट के कोष को उनके प्रावधान के अनुसार निपटाया जाना था। चूंकि निर्धारिती ट्रस्ट के खर्चों को चुकाने के बाद उपलब्ध ट्रस्ट फंड से आय के पूरे अवशेष का हकदार था, न कि किसी निर्दिष्ट या पूर्व-निर्धारित राशि का, गुजरात उच्च न्यायालय ने माना कि प्रत्येक ट्रस्ट के तहत निर्धारिती का अधिकार कर्म वार्षिकी नहीं थे बल्कि केवल जीवन हित के बराबर थे। गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले की बाद में इस न्यायालय ने कॉमरेड में पुष्टि की थी। वेल्थ टैक्स, गुजरात बनाम अरुंधति बालकृष्ण जिसमें यह इस प्रकार देखा गया था;

"तीन ट्रस्ट डीड में प्रासंगिक खंडों के विश्लेषण पर, यह स्पष्ट है कि निर्धारिती था इसके तहत ट्रस्ट पर तय किए गए फंड से होने वाली आय का एक हिस्सा दिया जाता है। उन कार्यों के तहत वह किसी भी निश्चित राशि की हकदार नहीं है। इसलिए, यह मानना संभव नहीं है कि वह उन कार्यों के तहत प्राप्त भुगतान की हकदार है। वार्षिकियां। निःसंदेह उन निधियों में उसका आजीवन हित है। अहमद सीएच आरिफ़ बनाम वेल्थ टैक्स के कमिश्नर, (1966) 59 आईटीआर 230 (कल.) में। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने माना कि किसी व्यक्ति का अधिकार वक्फ के तहत वक्फ संपत्ति की शुद्ध आय का एक अंश प्राप्त करना संपत्ति कर अधिनियम, 1957 के अर्थ में एक "संपत्ति" है, और इस तरह के अधिकार का पूंजी मूल्य संपत्ति कर के लिए मूल्यांकन योग्य है। इसमें, न्यायालय इस विवाद को खारिज कर दिया कि प्रश्न में अधिकार एक "वार्षिकी" था। इस निर्णय को इस न्यायालय ने अहमद जीएच आरिफ़ बनाम संपति कर आयुक्त, (1970) 76 आईटीआर 471 (1968 की सिविल अपील संख्या 2129-2132 पर 20 अगस्त 1969 को निर्णय लिया गया) में अनुमोदित किया और यह हमारे लिए बाध्यकारी है। इसी

तरह का दृष्टिकोण कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने भी अपनाया था। संपत्ति कर बनाम श्रीमती डोरोथी मार्टिन, (1968) 69 आईटीआर 586 (कल.)। उस मामले में, निर्धारिती के पिता की वसीयत के तहत, निर्धारिती अपने जीवन के लिए अवशिष्ट ट्रस्ट फंड में अपने हिस्से पर अर्जित वार्षिक ब्याज प्राप्त करने की हकदार थी। संपत्ति कर अधिकारी ने उक्त शेयर के पूरे मूल्य को निर्धारिती की मूल्यांकन योग्य संपत्ति में शामिल किया और संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 16 (3) के तहत कर के अधीन कर दिया। उस आदेश की पुष्टि अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा की गई थी।लेकिन अपील में ट्रिब्यूनल ने निर्धारिती की शुद्ध संपत्ति की गणना में इसे बाहर कर दिया। उच्च न्यायालय में किए गए एक संदर्भ पर, यह माना गया कि, वसीयत में विभिन्न खंडों के निर्माण पर, निर्धारिती अवशिष्ट ट्रस्ट फंड की सामान्य आय में एक अंशांश हिस्से का हकदार था, न कि समय-समय पर देय एक निश्चित राशि का। "वार्षिकी" और, इसलिए, उसके शेयर का मूल्य उसकी शुद्ध संपत्ति की गणना में शामिल की जाने वाली संपत्ति थी। हमारे विचार में ये निर्णय कानूनी स्थिति को सही ढंग से निर्धारित करते हैं। इस दृष्टि से, इस बात पर विचार करना

आवश्यक नहीं है कि क्या उन कार्यों के तहत निर्धारिती द्वारा प्राप्त होने वाली आय, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, एकमुश्त अनुदान में परिवर्तित होने में सक्षम है।

ऊपर उल्लिखित कारणों से, हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि तीन ट्रस्ट डीड के तहत निर्धारिती को किए जाने वाले भुगतान को वार्षिकी के रूप में नहीं माना जा सकता है, और, इसलिए, वह लाभ की हकदार नहीं है एस. 2 (ई) (iv) का."

हालाँकि, इस मामले में निर्धारिती की ओर से यह तर्क दिया गया है कि चूंकि ट्रस्ट फंड में सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल थीं जो ब्याज के माध्यम से निश्चित वार्षिक आय दे रही थीं और इसका कोई सबूत नहीं था उक्त प्रतिभूतियों को अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित कर दिया गया है; उच्च या निम्न आय प्राप्त करते हुए, यह माना जाना चाहिए कि निर्धारिती को दिया गया लाभ केवल वार्षिकी था और जीवन हित नहीं। इस तर्क को उसी कारण से खारिज किया जाना चाहिए जिसके लिए ए इसी तरह के विवाद को इस न्यायालय ने संपत्ति कर आयुक्त के मामले में खारिज कर दिया था । संपति कर आयुक्त राजस्थान बनाम गायत्री देवी, निम्नलिखित शब्दों में:-

"इन खंडों से यह स्पष्ट है कि महाराजा की मंशा थी कि करदाता को ट्रस्ट फंड की आय में आधा हिस्सा मिले। न तो ट्रस्ट फंड तय किया गया था और न ही निर्धारिती को देय राशि तय की गई थी। केवल एक बात निश्चित है कि वह ट्रस्ट फंड की आय में से 15/30 हिस्सेदारी की हकदार है। ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि वह जिस चीज़ की हकदार थी वह वार्षिकी नहीं थी बल्कि ट्रस्ट फंड की आय में एक हिस्सा था।

निर्धारिती के विद्वान वकील श्री सीतलवाड ने तर्क दिया कि जिस वर्ष हम चिंतित हैं, उस वर्ष के दौरान ट्रस्ट फंड में कोई बदलाव नहीं हुआ था और उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और जैसा कि हम दायित्व पर विचार कर रहे हैं संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए, हमारा यह मानना उचित होगा कि संबंधित वर्ष में निर्धारिती द्वारा प्राप्य राशि एक वार्षिकी थी। हमें इस विवाद में कोई ताकत नजर नहीं आती. यह प्रश्न कि कोई विशेष आय एक वार्षिकी है या नहीं, किसी विशेष वर्ष में प्राप्त राशि पर निर्भर नहीं करता है। हमें यह देखना होगा कि ट्रस्ट बनाने में महाराजा की मंशा वास्तव में क्या थी। क्या उसका इरादा निर्धारिती को हर साल एक पूर्व-निर्धारित राशि देने का था या क्या वह उसे किसी फंड की आय में एक अंश हिस्सा देने का इरादा रखता था? उस प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता है और वह है। उसका इरादा उसे ट्रस्ट फंड की आय में एक अंश हिस्सा देने का था। एक आय एक वर्ष में वार्षिकी और दूसरे वर्ष में एक विभाज्य शेयर नहीं हो सकती। यह साल-दर-साल अपना चरित्र नहीं बदल सकता। पाए गए तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि करदाता का ट्रस्ट फंड में आजीवन हित है"

आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय संपति कर आयुक्त ए.पी. बनाम नवाब फरीद नवाज जंग व अन्य जिस पर उच्च न्यायालय ने इस मामले में इस हद तक भरोसा किया है कि इसके विपरीत दृष्टिकोण को गलत माना जाना चाहिए।

अब हम इन-रे ड्यूक ऑफ नॉरफ़ॉक के फैसले पर विचार कर सकते हैं। पब्लिक ट्रस्टी बनाम इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर, जिस पर उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में बहुत अधिक भरोसा किया था। जो बिंदु विचार के लिए उठा था उपरोक्त मामला यह था कि क्या, जहां दो या दो से अधिक जीवन के लिए एक सतत वार्षिकी उत्तराधिकार में दो या दो से अधिक व्यक्तियों को दी गई थी और संपत्ति पर लगाया गया था, किसी भी वार्षिकीधारक की मृत्यु पर, मरने वाले अंतिम व्यक्ति के अलावा, संपत्ति शुल्क धारा 1 के तहत देय था। वित्त अधिनियम, 1894 इस आधार पर कि यह वार्षिकी है जो वार्षिकीधारक की मृत्यु पर पारित होती है। संपत्ति शुल्क अधिकारियों ने वार्षिकीग्राही की मृत्यु पर संपत्ति शुल्क का दावा किया, जो मरने वाले वार्षिकीधारकों में से अंतिम नहीं था, के टुकड़े पर वार्षिकी का उत्पादन करने के लिए आवश्यक पूंजी, इस आधार पर कि वार्षिकीधारक के रूप में, मृतक को वार्षिकी के साथ लगाई गई पूंजी पर ब्याज था और उस ब्याज की समाप्ति ने वित्त अधिनियम 1894 की धारा 2 (1) (बी) के तहत कर योग्य लाभ को जन्म दिया। सार्वजनिक ट्रस्टी, जिसमें संपत्ति निहित थी, ने दावा किया कि संपत्ति शुल्क उस वार्षिकीग्राही के जीवन के लिए निरंतर वार्षिकी के मूल्य पर देय हो गया है जो मृत वार्षिकीग्राही की मृत्यु पर वार्षिकी में सफल हुआ था। जेनकिंस एलजे ने अपने फैसले के दौरान, उपरोक्त मामले में वार्षिकी और जीवन हित के बीच अंतर को इस प्रकार समझाया:

"संपत्ति पर लगाया गया वार्षिकी किसी भी तरह से संपत्ति की पूंजी के अनुपात में ब्याज के बराबर नहीं है जो इसकी वार्षिक राशि का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त है। यह इससे अधिक या कम कुछ भी नहीं है पूरी संपत्ति की आय में से निर्धारित वार्षिक राशि प्राप्त करने का अधिकार (और कई मामलों में आय की कमी की स्थिति में पूंजी से बाहर)। यह चार्ज की गई संपत्ति के किसी विशेष हिस्से में कोई ब्याज नहीं देता है, लेकिन केवल एक सुरक्षा जो पूरी तरह से फैली हुई है। वार्षिकीकर्ता निर्धारित राशि से न तो कम और न ही अधिक प्राप्त करने का हकदार है। अब तक को छोड़कर, संपत्ति द्वारा उत्पादित आय की मात्रा में न तो उसे वृद्धि से लाभ होता है और न ही गिरावट से हानि होती है। क्योंकि ऐसे मामले में आय की कमी हो सकती है जिसमें पूंजी का सहारा शामिल नहीं है।

दूसरी ओर, संपत्ति की आय के एक हिस्से में जीवन भर का ब्याज बराबर है, और वास्तव में बनता है, आय के हिस्से के अनुरूप पूंजी के हिस्से में जीवन हित। जीवन किरायेदार को आय का हिस्सा प्राप्त होता है, चाहे वह कितना भी हो, और उसका ब्याज, जिसे पूंजी में जीवन हित के रूप में देखा जाता है, में पूरी संपत्ति का एक स्थिर अनुपात होता है, चाहे आय बड़ी हो या छोटी, और चाहे पूंजी मूल्य हो संपत्ति बढ़ती है या गिरती है। जो संपत्ति उसकी मृत्यु पर बदल जाती है (या दूसरे शब्दों में धारा 1 के तहत गुजरती है) इस प्रकार स्पष्ट रूप से पूंजी का निर्दिष्ट हिस्सा शामिल होता है, जो उसके लाभकारी आनंद से दूसरे के पास चला जाता है। एक वार्षिकी पूंजी के किसी भी निश्चित अनुपात से संबंधित नहीं हो सकती है: डी ट्रैफर्ड बनाम अटॉर्नी जनरल, 1935 एसी 280।''

एवरसेड एम.आर. जिन्होंने सहमति व्यक्त करते हुये अपना अलग निर्णय दिया और कथित किया:

"उस व्यक्ति के मामले में जिसने अपने जीवन में किसी संपत्ति की आय का एक-चौथाई (मान लीजिए) आनंद लिया है, यह मुझे सामान्य ज्ञान और भाषा के स्वाभाविक उपयोग के अनुरूप लगता है यह कहने के लिए कि उसने अपने जीवन का आनंद लिया, कि वह संपत्ति के एक चौथाई हिस्से का आजीवन किरायेदार था; और, तदनुसार, उसकी मृत्यु पर संपत्ति का एक चौथाई हिस्सा अगले उत्तराधिकारी को चला गया। लेकिन मेरे विचार से, ऐसी किसी भी भाषा का उपयोग वार्षिकीधारक के मामले में उचित रूप से नहीं किया जा सकता है। उसे किसी भी तरह से संपत्ति की उपज में बदलाव से कोई सरोकार नहीं है: उसकी वार्षिकी पर उसका अधिकार जारी रहेगा, चाहे संपत्ति से कितनी भी आय हो या (जब तक कि उसे केवल आय देखने का अधिकार न हो) भले ही संपत्ति से कोई आय न हो।"

रोल्स के विद्वान मास्टर ने इन रे नॉर्थक्लिफ और क्रिस्टी बनाम लॉर्ड एडवोकेट, के मामलों को अपने पहले के मामले से इस प्रकार अलग किया:

"दोनों अंतिम-उल्लेखित मामले उत्तराधिकार में आनंद लेने के लिए संपत्ति की सामान्य आय के विभाज्य शेयरों के स्वभाव के उदाहरण थे, जो वार्षिकी या वार्षिक राशि से अलग थे, जो परिवर्तनीय होते हुए भी (जैसे) इन री कैसल के मामले में, (1927) 2 अध्याय 275) किसी भी तरह से संपत्ति की सामान्य आय पर निर्भर या उससे संबंधित नहीं है।

तदनुसार क्राउन का तर्क खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त निर्णय को ध्यान से पढ़ने पर, हमें वर्तमान मामले में निर्धारिती की ओर से दिए गए तर्क के लिए कोई समर्थन नहीं मिलता है। निर्णय इस बिंदु पर बिल्कुल स्पष्ट है कि जब भुगतान कॉर्पस की आय पर निर्भर होता है, तो यह इसे वार्षिकी नहीं कहा जा सकता है और यह वार्षिकी भले ही परिवर्तनशील हो सकती है जैसा कि इन री, कैसल, (1927) 2 अध्याय 275 के मामले में किसी भी तरह से संपत्ति की सामान्य आय पर निर्भर या संबंधित नहीं हो सकती है। इसलिए, कोर्ट ने ड्यूक ऑफ नोरफोक: इन री पब्लिक ट्रस्टी,(सुप्रा) में दिए गए भुगतान में भिन्नता की संभावना के अस्तित्व के बावजूद निर्णय पर भरोसा करने में गलती की। उपरोक्त मामले में निर्धारिती को ट्रस्ट डीड के

निष्पादन के समय हस्तांतरित किसी भी प्रतिभूति के मोचन पर ट्रस्टी द्वारा प्राप्त की जाने वाली नई प्रतिभूतियों की आय के आधार पर, भुगतान एक वार्षिकी के बराबर होगा।"

हमारे सामने उद्धृत निर्णयों पर विचार करने पर, हमें लगता है कि एक वार्षिकी बनाने के लिए, समय-समय पर किया जाने वाला भुगतान एक निश्चित या पूर्व-निर्धारित होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए इस तरह के भुगतान के लिए ली जाने वाली निधि या संपत्ति की सामान्य आय से संबंधित किसी भी आधार पर या उसके आधार पर किसी भी बदलाव के लिए उत्तरदायी होगा। वर्तमान मामले में, जैसा कि गायत्री देवी (सुप्रा) के मामले में देखा गया है, हमें जो देखना है वह सेटलर का इरादा है, क्या वह चाहता था कि निर्धारिती को पूर्व-निर्धारित मिलना चाहिए प्रत्येक वर्ष राशि या क्या निर्धारिती को ट्रस्ट फंड की पूरी शुद्ध आय मिलनी चाहिए। चूंकि सेटलर का इरादा निर्विवाद रूप से बाद वाला था, इसलिए निर्धारिती के अधिकार को वार्षिकी के रूप में नहीं माना जा सकता है। एक अतिरिक्त कारक जिसके लिए हमें समान दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, वह यह है कि ट्रस्ट डीड के तहत ट्रस्टियों को सरकारी प्रतिभूतियों की आय को फिर से निवेश करने की शक्ति दी गई थी, जिससे आय में भिन्नता की संभावना होती है और परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाली राशि में भिन्नता होती है। निर्धारिती द्वारा. तथ्य यह है कि प्रासंगिक वर्षों के दौरान ऐसा कोई पुनर्निवेश नहीं हुआ था, यह महत्वहीन है। पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, अपीले स्वीकार की जाती हैं, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया जाता है और अधिनियम की धारा 27 (1) के तहत उच्च न्यायालय को संदर्भित प्रश्न का उत्तर नकारात्मक और निर्धारिती के विरुद्ध

दिया जाता है। मामले की परिस्थितियों में, निर्धारिती, विभाग के खर्च का भुगतान करेगा। (सुनवाई शुल्क एक सेट).

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुरेन्द्र चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानिय भाषा में अनुवादित किया गया है ओर किसी अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक ओर अधिकारिक उददेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा ओर निष्पादन व कार्यान्वयन के उददेश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।